(1975) 2 SCR 425

सीताला प्रसाद शॉ

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य

15 अक्टूबर, 1974

[वाई. वी. चंद्रचूड और आर. एस. सरकारिया, जे. जे.]

भारत का संविधान, धारा 22 (5) — आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम,1971- नज़रबंदी की अवधि-बंदी प्रत्यक्षीकरण- नज़रबंदी के आधार एक एकल घटना को संदर्भित करते हैं- ऐसा विवरण प्रस्तुत किया गया कि आप सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल "कार्य कर रहे हैं" - यदि यह निष्कर्ष उचित ठहराता है कि नज़रबंदी आदेश अज्ञात सामग्री पर आधारित है।

याचिकाकर्ता को आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम, 1971 के तहत हिरासत में लिया गया था। नजरबंदी का आधार एक अकेली घटना को संदर्भित करता है। याचिकाकर्ता को दिए गए विवरण में हालांकि कहा गया है कि उसे निम्न आधार पर हिरासत में लिया गया थाः आप सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल "कार्य कर रहे हैं"। बंदी

प्रत्यक्षीकरण के लिए एक याचिका में यह तर्क दिया गया था कि चूंकि उपयोग की गई भाषा लंबे समय तक एक दोषपूर्ण आचरण को दर्शाती है, इसलिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के पास यह दिखाने वाली सामग्री थी कि याचिकाकर्ता लंबे समय तक आपराधिक आचरण में लिप्त था और चूंकि ऐसी सामग्री का याचिकाकर्ता को खुलासा नहीं किया गया था, इसलिए उसे इसे पूरा करने का कोई अवसर नहीं मिला, जिसके परिणामस्वरूप संविधान कि धारा 22 (5) का उल्लंघन हुआ। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को दिए गए आदेश में दिखाई गई तारीख से अलग तारीख वाले एक निरोध आदेश को मंजूरी दी थी, इसलिए राज्य सरकार के पास याचिकाकर्ता की नजरबंदी को मंजूरी देते समय उसके समक्ष निरोध का कोई अन्य आदेश था।

नजरबंदी के आदेश की पुष्टि करते हुए, अभिनिर्धारित:

(1) व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में, हिरासत में लेने वाले अधिकारी को अपने कार्यों के निर्वहन में सबसे अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन यह निरोध आदेशों के अवास्तविक विच्छेदन को उचित नहीं ठहराता हैं। राज्य द्वारा दाखिल किया गया जवाबी हलफनामा यह दर्शाता है कि किसी अन्य सामग्री पर ध्यान नहीं दिया गया। इस अभिव्यक्ति का उपयोग कि "आप कर रहे हैं", हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन उस दलील का

समर्थन नहीं करता कि निरोध आदेश अज्ञात सामग्री पर आधारित था। [426 सी-ई]

(2) अनुमोदन के आदेश में एक टंकण संबंधी त्रुटि है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि निरोध आदेश की संख्या सही ढंग से दी गई है और निरोध आदेश को पुख्ता करने वाले आदेश में, सलाहकार बोर्ड के परामर्श के बाद सही है निरोध आदेश की तिथि का उल्लेख किया गया है। [426 एफ-एच]

मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका संख्या 118/1974

संविधान की धारा 32 के तहत याचिका।

याचिकाकर्ता की ओर से आरएल कोहली।

प्रतिवादी के लिए दिलीप सिन्हा और जी. एस. चटर्जी।

न्यायालय का निर्णय चंद्रचूड़, जे. द्वारा दिया गया था-

याचिकाकर्ता को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971 के तहत जिला मजिस्ट्रेट, हावड़ा द्वारा पारित 23 अगस्त, 1973 के एक आदेश द्वारा हिरासत में लिया गया था। आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से हिरासत में लिया गया।

हिरासत के आधार का विवरण 18 मार्च, 1973 की एक एकांत घटना को संदर्भित करता है। आरोप है कि उस दिन दोपहर लगभग 2 बजे, याचिकाकर्ता और उसके सहयोगियों ने तलवारों, बल्लम और लाठियों से लैस होकर राजनारायण रॉय चौधरी घाट रोड, शिबपुर, हावड़ा में बंगालियों के एक समूह पर हमला किया जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। आगे कहा गया है कि इस आचरण से इलाके में आतंक का राज फैल गया, जिसके परिणामस्वरूप दुकानें और सड़क किनारे के घरों की दुकाने और दरवाजे बंद हो गए, इलाके के लोग घबराकर भाग गए और लोग आम तौर पर मारपीट के डर से अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए इस याचिका में हमारे विचार के लिए दो बिंदु उठाए हैं। याचिकाकर्ता को दिए गए विवरण में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को इस आधार पर हिरासत में लिया गया था: "आप सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल तरीके से कार्य कर रहे हैं"। तर्क यह है कि आदेश एक ही घटना पर आधारित है और इसलिए, यह दर्शाने वाली भाषा का उपयोग कि याचिकाकर्ता काफी लंबे समय तक दोषी आचरण में लिप्त था पूरी तरह से अनुचित था। निष्कर्ष के तौर यह आग्रह किया गया कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के पास ऐसी सामग्री थी जो दर्शाती है कि याचिकाकर्ता लंबे समय से आपराधिक आचरण में शामिल था और चूंकि

ऐसी सामग्री याचिकाकर्ता को नहीं बताई गई थी, इसलिए उसे इसे जानने का कोई अवसर नहीं मिला, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन का हुआ है। हम इस दलील से प्रभावित नहीं हैं। यह सच है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में, हिरासत में लेने वाले अधिकारियों को अपने कार्यों के निर्वहन में सबसे अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन यह हिरासत के आदेशों के अवास्तविक विच्छेदन को उचित नहीं ठहराता। राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया गया जो यह दर्शाता है कि हिरासत का आदेश पारित करते समय हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य सामग्री पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए, अभिव्यक्ति का उपयोग, "आप कार्य कर रहे हैं" हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है, इस दलील का समर्थन नहीं करता है कि हिरासत का आदेश अज्ञात सामग्री पर आधारित है। याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया था कि वह सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के विपरीत कार्य कर रहा था "जैसा कि उसे दिए गए विवरणों से पता चलता है"। विवरण केवल एक ही घटना का उल्लेख करते हैं।

नजरबंदी आदेश पर हमले का दूसरा आधार यह है कि जब राज्य सरकार ने 30 अगस्त, 1973 को नजरबंदी को मंजूरी दी तो उसने नजरबंदी आदेश दिनांकित 25-8-73 को मंजूरी देते हुए एक आदेश पारित किया। चूंकि हिरासत का आक्षेपित आदेश 23 अगस्त 1973 का है, इसलिए

यह आग्रह किया जाता है कि याचिकाकर्ता की नजरबंदी को मंजूरी देते समय, राज्य सरकार के पास नजरबंदी का कोई अन्य आदेश था। इस दलील में कोई दम नहीं है। अनुमोदन के आदेश में मुद्रण संबंधी त्रुटि है। यह बात राज्य सरकार द्वारा 8 नवंबर, 1973 को पारित आदेश से स्पष्ट है जिसमें सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त करने के बाद हिरासत के आदेश की पुष्टि की गई है। पुष्टिकरण का आदेश 23 अगस्त 1973 के हिरासत के आदेश को संदर्भित करता है। यह भी कहा जाना चाहिए कि जैसा कि पुष्टि के आदेश में है, वैसे ही अनुमोदन के आदेश में, नजरबंदी आदेश संख्या 1818-सी का एक स्पष्ट संदर्भ दिया गया है। 23 अगस्त, 1973 को याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित हिरासत के आदेश में वही संख्या है जो दर्शाता है कि अनुमोदन के आदेश में दिनांक "25-8-73" के आदेश का संदर्भ एक टंकण संबंधी गलती है। परिणामस्वरूप, हम हिरासत के आदेश की पुष्टि करते हैं और इस याचिका में नियम का निर्वहन करते हैं।

पीएच. पी. याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।